भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1457
13.02.2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन से किसानों को लाभ

1457. श्री आलोक शर्मा:

श्री गणेश सिंह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) परियोजनाओं के कार्यान्वयन से विशेषकर मूल्य वृद्धि और कृषि क्षेत्र में लाभ के संदर्भ में किसानों को होने वाले प्रत्यक्ष लाभ का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पीएमकेएसवाई उक्त योजना खाद्य प्रसंस्करण, विशेषकर प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में सतत प्रथाओं को किस प्रकार बढ़ावा देती है;
- (ग) क्या इस योजना की प्रभावकारिता में और सुधार करने के लिए कोई नई योजनाएं या संघटक शुरू किए जा रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, उद्यमियों को खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है, जिससे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसका 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल परिव्यय 5520 करोड़ रुपये है। खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से बर्बादी कम होती है और कृषि उपज की मांग बढ़ती है, जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति होती है। पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत, योजना की शुरुआत से कुल 1646 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1087 पूर्ण/संचालित हैं, जिनसे 3317538

किसान लाभान्वित हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में पीएमकेएसवाई के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-1** में है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अवसंरचना के निर्माण, बिक्री आधारित प्रोत्साहनों के अनुदान, क्षमता विस्तार और अन्य सहायक उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जल और वायु के संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड/एजेंसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ) अनुमोदित परियोजनाओं को अनुदान सहायता/सब्सिडी की किस्त जारी करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को नॉन-ओडीएस (गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थ) और निम्न जीडब्ल्यूपी (निम्न ग्लोबल वार्मिंग क्षमता) रेफ्रिजरेंट्स-आधारित ऊर्जा कुशल शीतलन प्रणालियों के उपयोग के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कोल्ड चैन अवसंरचना की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है।

पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के तहत, परियोजना के लिए नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, बायोमास, पवन, आदि) के लिए भी सहायता प्राप्त की जा सकती है (अधिकतम पात्र अनुमेय लागत प्रति परियोजना 35 लाख रुपये है)। देश भर से पात्र संस्थाएँ आवेदन कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान - तंजावुर ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पॉली लैक्टिक एसिड (पीएलए), स्टार्च, नैनो फाइबर आदि जैसे बायोपॉलिमर्स से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधान के विकास के माध्यम से टिकाऊ पैकेजिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विकसित करने के प्रयास किए हैं।

(ग) एवं (घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध- 1

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन से किसानों को लाभ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1457 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध पिछले पांच वर्षों में पीएमकेएसवाई के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित किसानों की संख्या
20-2019	435008
21-2020	621100
22-2021	345565
23-2022	214351
24-2023	222861
25-2024	63458